राज्य सरकारों द्वारा बजट आबंटन, उपलब्ध संसाधनों तथा विभिन्न स्कीमों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए तय किए जाते हैं। भारत सरकार, राज्यों पर चालू परियोजनाओं को अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर शीघ्र पूरा करने के लिए जोर डाल रही है। 1983-84 के दौरान विद्युत क्षेत्र में परिव्यय को पृथक-रक्षित माना गया है।

टेहरी बांध

2027. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने टेहरी बांध के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृत प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है और इस पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की आजीविका के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 1972 में 197.92 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश के टिहरी बहु-प्रयोजनी बांध परियोजना को अनुमादित किया था। राज्य सरकार ने 1979 में 827.30 करोड़ रु० के अनुमानित लागत के साथ इसके आकार में परिवर्तन करके परियोजना को संशोधित किया था। योजना आयोग द्वारा संशोधित स्कीम को अभी अनुमोदित किया किया जाना है। सिंचाई तथा विद्युत सेक्टरों के अन्तर्गत एक साथ छठी योजना में परियोजना के लिए 216 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। मार्च, 1980 तक (छठी योजना के शुरू में) किया गया कुल व्यय 51.27 करोड़ रुपए है। छठी योजना के पहले तीन वर्षों में 66.01 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं तथा राज्य सरकार द्वारा 1983-84 के लिए 30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पुनर्वास योजना तैयार की है जिसमें टिहरी बांध के निर्माण से स्थापित व्यक्तियों को सड़क, जल-सप्लाई, स्वच्छता, स्कूल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए नए विस्थापित क्षेत्रों में बसाया जाएगा। परियोजना रिपोर्ट में भूमि के लिए मुआवजा दिए जाने के साथ-साथ आवास निर्माण के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी करना, परियोजना को दी गई दरों पर आवास निर्माण सामग्री सप्लाई करने के साथ-साथ घरेलू सामान को शिफ्ट करने के लिए उदारता के आधार पर अन्य अनुदान देने की व्यवस्था है। ग्रामीण परिवारों को भूमि के बदले भूमि दिए जाने के आधार पर 2 एकड़ से कम नहीं और 12½ एकड़ तक प्रति परिवार को कृषि के लिए विकसित भूमि देकर पुनर्वास करने का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि भूमिहीन कृषि-मजदूर परिवारों को भी कम से कम 2 एकड़ भूमि दी जाएगी। वर्तमान टिहरी शहर को सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि की सुविधाएं प्रदान करते हुए एक नए टाउनशिप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसके निर्माण-काल के दौरान इस परियोजना से और अधिक रोजगार के अवसर दिए जाने की संभावना है।

Report by study group on shifting Cultivation and Encroachment

2028. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Study Groups on Shifting Cultivation and Enchroachment have submitted their reports to his Ministry ;

(b) if so, the main recommendations of these Groups therefor, Group-wise,

(c) whether the reports and recommendations have been examined by his Ministry ;

(d) if so, the recommendations so far accepted implemented by Government ; and

(e) the reaction and action of the States for the implementation of these recommendations concerning their States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) to (e) 'Of the' two Task Forces constituted separately on Shifting Cultivation and forest Encroachments, only the Task Force on Shifting Cultivation has submitted its report on 28th October, 1983. The report is under consideration.

Badanalla Medium Irrigation Project

2029. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the World Bank had agreed to provide loan assistance for Badanalla Medium Irrigation Project in Orissa ;

(b) if so, the funds so far released by the World Bank ;

(c) whether Government of Orissa have given the administrative approval to this project soon after the clearance from the Planning Commission as Sixth Plan Project ;

(d) if so, when it was cleared and approved by the State Government for execution ;

(e) funds so far provided and progress made in execution ; and

(f) if it was delayed, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) Yes, Sir ; The Badanalla Medium Irrigation Project was taken up for implementation under the IDA ASSISTED Orissa Irrigation Project II (Cr. No. 740-IN). The credit of US $58.0 million stands fully utilised. It has now been included for completion in the Medium line of credit by the World Bank and the Project has been signed for credit of US $ 105 million in September 1983, which is expected to be declared effective shortly by the Bank.

(c) and (d) Project was cleared by Planning Commission on 7.1.1981 and administratively approved by State Government on 23.10.1982.

(e) (a) above indicates the overall utilization of funds for the World Bank Project. The Progress under individual MIP under the project is within the purview of State Government.

(f) Question does not arise.

Inclusion of States Land Reform Acts in Ninth Schedule of the Constitution

2030. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the names of the States whose Land Reform Acts have been considered by his Ministry for inclusion in Ninth Schedule of the Constitution as suggested by the States ;

(b) whether some States have also suggested to include the Acts relating to Alienation of Tribal Lands in Ninth Schedule along with the Land Reform Acts ;

(c) if so, the names of such States ; and

(d) the steps taken by his Ministry to include these Acts under Ninth Schedule, keeping in view the speedy implementation of land reform measures by the States ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) Certain land laws enacted by Assam, Bihar, Haryana, Tamil Nadu, U. P., West Bengal and Goa, Daman & Diu have been considered and included in the Constitution (Forty-Eighth Amendment) Bill, 1983 for being placed in the Ninth Schedule to the Constitution.

(b) to (d) A number of land laws already included in the Ninth Schedule deal with alienation of tribal lands. Suggestions for inclusion of some more laws have been received from a number of States and examined. These States include Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Manipur, Madhya Pradesh, Orissa and West Bengal. Inclusion of laws in the